



संपादकीय

कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है

कई बार कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। जो घटना कहीं पर एक बार होती है, वही घटना फिर किसी दूसरी जगह पर होती है या होने की संभावना रहती है तो कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। इतिहास अपने को इसलिए भी दोहराता भी है कि एक बार जो गलती आदमी या पार्टी करती है और उससे सबक नहीं लेती है और वही गलती दोबारा करती है तो फिर से वही सब होने की संभावना रहती है जो एक बार की गई गलती के कारण इतिहास में दर्ज है। कर्नाटक कांग्रेस में देखा जा रहा है कि फिर से वही दोहराया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में दोहराया जा चुका है। कर्नाटक कांग्रेस व सरकार में फिर से वही सब हो रहा है जो एक बार छत्तीसगढ़ में हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। यानी कांग्रेस के जितने गुट थे सबने कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और 15 साल के बाद भाजपा को हराने में सफल हुए थे। कुछ लोग इसका श्रेय अकेले भूपेश बघेल को देते हैं कि उन्होंने गुटों में बंटे हुए कांग्रेस को एकजुट कर कांग्रेस के लिए जो 15 साल से असंभव काम था, वह कर दिखाया था। कई लोगों के नामों की चर्चा थी सीएम के लिए। आखिरी में दो लोग ही सीएम के दावेदार के रूप में बच गए थे। दोनों ही सीएम बनना चाहते थे, कोई पीछे हटने के तैयार नहीं हुआ तो माना जाता है कि आलाकमान ने बीच का रास्ता यह निकाला था कि दोनों ढाई-ढाई साल सीएम पद पर रहेंगे। इस तरह पहले ढाई साल भूपेश बघेल को सीएम रहना था और उसके बाद के ढाई साल टीएस सिंहदेव को सीएम बनना था। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव से ज्यादा होशियार थे, वह पहले सीएम बने और ढाई साल बाद भी सीएम की कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। आलाकमान को बता दिया कि सारे लोग तो चाहते हैं कि मैं ही सीएम बना रहूं। यानी सब मेरे साथ है, इसलिए सीएम तो उन्हें ही बने रहना चाहिए जिसके साथ सब हैं। आलाकमान ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखा और टीएस सिंहदेव का डिटी सीएम बनाकर संतुष्ट किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल अकेले चुनाव नहीं जिता सके। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार नहीं बना सकी।

माना जाता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर आलाकमान ने वही गलती की जो उसने छत्तीसगढ़ में की थी। यहां भी सिध्दारमेया व शिवकुमार दोनों सीएम बनना चाहते थे, दोनों से यहां भी कह दिया गया मामला सुलझाने के लिए कि सिध्दारमेया ढाई साल सीएम रहेंगे और उसके बाद ढाई साल शिवशंकर ढाई साल सीएम रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ था यानी सिध्दारमेया का समय पूरा होने को है, इसलिए फिर एक बार कर्नाटक में सीएम पद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताने में टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका थी, वैसे ही कर्नाटक चुनाव जिताने में शिवकुमार की अहम भूमिका थी। अब शिवकुमार चाहते हैं कि आलाकमान अपना वादा पूरा करे। सिध्दारमेया भूपेश बघेल की तरह सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मामले को समझने कर्नाटक सुरजेवाला को भेजा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने कह दिया है कि इस मामले में जो कुछ फैसला होगा आलाकमान करेगा। आलाकमान क्या करेगा किसी तो पता नहीं है सीएम जो बन जाता है वह पद को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वह भूपेश बघेल हो या सिध्दारमेया हो। भूपेश बघेल के सीएम पद नहीं छोड़ने पर इसका खामियाजा पार्टी को छत्तीसगढ़ में भुगताना पड़ा था। माना जा रहा था कि कांग्रेस को यहां को भाजपा नहीं हरा सकती लेकिन हुआ क्या भाजपा ने कांग्रेस को हरा दिया। यानी हकीकत कुछ और थी और हकीकत कुछ और बताया जा रहा था। सिध्दारमेया को कर्नाटक में सीएम बनाए रखा गया तो हो सकता है कि वहां इतिहास अपने को दोहराए। कर्नाटक में भी अगले चुनाव में वही हो जो छत्तीसगढ़ में हुआ था।

विचार

मध्यमवर्गीय परिवार नहीं फंसे ऋण के जाल में

प्रहलाद सबनानी (सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके।

भारत में चूँकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं।

बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस -णराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी



कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें। क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत् प्राप्त छूट के

भारत का कायाकल्प: मोदी नेतृत्व प्रभाव

मानदंड	2014	2025
कपास एमएसपी मीडियम स्टेपल	3700 रुपए	7710 रुपए
भारतीय कपास निगम की खरीद	22.86 लाख गांठ	100 लाख गांठ
रेशम क्षेत्र में रोजगार	78 लाख	98 लाख
रेशम उत्पादन	26,000 मीट्रिक टन	41,115 मीट्रिक टन
जूट विविधीकृत उत्पादों का कुल निर्यात	1,470 करोड़ रुपए	3,000 करोड़ रुपए से अधिक
हस्तशिल्प निर्यात	29,000 करोड़ रुपए	49,000 करोड़ रुपए
तकनीकी वस्त्र निर्यात	नगण्य	3 बिलियन डॉलर

मित्र पार्क के जरिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के मिशन के रूप में नए युग के निवेश के माध्यम से फिर से बुना गया है।

भारत के वस्त्र क्षेत्र में रोजगार 2014 में 3 करोड़ से तेजी से बढ़कर आज 4.6 करोड़ हो गया है, जिससे कुशल और अकुशल श्रम को अवशोषित करने के अवसर और क्षमता दोनों में मजबूत विस्तार हुआ है। घरेलू मांग में वृद्धि और उत्पादन की तेजी से प्रेरित होकर बाजार का आकार 112 बिलियन डॉलर से बढ़कर 176 बिलियन डॉलर हो गया है। परिधान निर्यात लंबे समय से इस क्षेत्र की आधारशिला है, वह 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर हो गया है, जो मूल्यवर्धित उत्पादन में लगातार लाभ को दर्शाता है। काफी समय से लॉबित भारत-यूके एक्ट्रीए को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतिम रूप दिया गया है। यह भारत के श्रम-प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए विनिर्माण और निर्यात के एक वैश्विक केंद्र के रूप में राष्ट्र के उत्थान के लिए द्वार खोलकर निर्णायक बढ़त का वादा करता है।

लेकिन ये मात्र आंकड़े नहीं हैं बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। वे एक रणनीतिक रीसेट का संकेत देते हैं। अस्थायी उपायों से दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, हमारी सरकार ने मानव निर्मित रेशों, नए युग के रेशों और तकनीकी वस्त्रों को आपनाने के लिए उद्योग के दायरे को उसके कॉटन कोर से आगे बढ़ाया है। जिन क्षेत्रों को कभी अनदेखा किया गया था, वे अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। यह विजन अब केवल घरेलू धागों तक सीमित नहीं है। यह भारत के वस्त्रों को लचीलेपन, कौशल और स्थिरता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने पर आधारित है। यह परिवर्तन संयोग से नहीं हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रित शासन, साहसिक सुधारों और अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है।

कपास के खेतों से कार्बन फाइबर तक विस्तार

भारत की वस्त्र गाथा आज पारंपरिक धागों से कहीं आगे है, जो कपास के खेतों से लेकर कार्बन फाइबर तक, हथकरघा से लेकर उच्च निष्पादन वाले तकनीकी वस्त्रों तक फैली हुई है। जमीनी स्तर पर, सरकार ने प्राकृतिक रेशों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। कपास उत्पादकता के लिए नए मिशन के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक कपास उत्पादन को 5.70 से 7.70 एमएमटी और उत्पादकता को 439 से 612 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाना है। वर्तमान में, कपास वैश्विक कपास निर्यात बाजार का 3.16 प्रतिशत और कस्तूरी कपास का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत, हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे प्रीमियम वैश्विक कपास निर्यात का 10 प्रतिशत बनाना है। पिछले 11 वर्षों में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद में 338 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यम और लंबे रेशे वाले कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुने से अधिक हो गए हैं, जिससे किसानों को सीधा

प्रगति का आधार-नवाचार, समावेश और पहचान का एक दशक



गिरिराज सिंह, केंद्रीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार

हम वस्त्रों की बात अवसर व्यापार की भाषा जैसे निर्यात, घाटा और अधिशेष के रूप में करते हैं। लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण उस पैमाने से चूक जाता है जो वास्तव में काम कर रहा है। भारत के वस्त्र क्षेत्र की ताकत केवल उसके विदेशी शिपमेंट में ही नहीं है। यह कहीं ज्यादा स्थायी चीजों में निहित है। बढ़ती जनसंख्या, एक ऐसा घरेलू ईंजन है जो धीमे होने से इन्फ्राकृत करता है और यह विरासत और नवाचार दोनों के उभरते हुए स्म्भाव को दर्शाता है। यह 143 करोड़ भारतीयों द्वारा संचालित है जो अपने पहनावे, अपने घरों और अपनी परंपराओं में आराम, पहचान और आकांक्षा बनाए रखते हैं।

इस क्रांति का प्रसारण नहीं किया गया। इसे बुना गया। जहां दुनिया डिजिटल सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे में तेजी को ट्रैक कर रही थी, वहीं भारत के चरणों पर कुछ शांत और गहरा सामने आ रहा था। जिस को कभी विरासत उद्योग के रूप में खारिज कर दिया गया था आज प्रथापंमत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे लचीलेपन, नवाचार और गौरव की शक्ति में बदल दिया गया है। भागलपुर के चमकते रेशम से लेकर पानीपत के पुनर्क्रिंत धागों तक, परिवर्तन धीरा, स्थिर और स्थायी है। यह पुनरुत्थान नहीं है। यह पुनर्जागरण है। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए नींव को कंक्रीट और इस्पात से आगे ले जाना होगा। उन्हें समुदायों, आजीविका और सांस्कृतिक निरंतरता पर आधारित होना चाहिए। वस्त्र क्षेत्र की तुलना में इस दृष्टिकोण को कहीं और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया गया है। 4.6 करोड़ लोगों के साथ दूसरा सबसे बड़ा निर्यात होने के नाते, यह एक उद्योग से अधिक है। यह कौशल, पहचान और अवसरों का जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। कभी पिछड़ा समझे जाने वाला यह उद्योग धीरे-धीरे आधुनिक आर्थिक इंजन में बदल गया है। अब पारंपरिक बुनाई वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर रही है, जबकि तकनीकी वस्त्र एयरोस्पेस और कृषि में अपनी पैठ बना रहे हैं। और जमीनी स्तर पर, प्रत्येक करघा और चरखा गरिमा, नवीनीकरण और शांत शक्ति की गहरी कहानी दर्शाता है।

विकास का एक दशक: आंकड़े जो बताते हैं एक कहानी

जब हमारी सरकार ने 2014 में कार्यभार ग्रहण किया था, तो भारत का वस्त्र क्षेत्र विरासत में निहित एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में दिशाहीन था। कभी उधराव से चिढ़ित, वस्त्र क्षेत्र के पैमाने और संरचना को समर्थ के तहत लक्षित कौशल, कपास उत्पादकता मिशन, पीएलआई योजना और पीएम

चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है।

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्शोधों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ोसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ोसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ोसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाडय वर्ग यदि बैंक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतान करना स्वयं उनके हित में हैं, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें।

भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उसने ही पैर पसारने चाहिए। अर्थात, नागरिकों को बैंकों से ऋण लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने लायक उनकी अतिरिक्त आय होनी चाहिए, ताकि ऋण की किश्तों एवं ब्याज की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके एवं उनका ऋण खता गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित नहीं हो।

बदलाव का संकेत है।

2030 तक इस क्षेत्र के मूल्य को दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करने के लक्ष्य के साथ, स्थिरता अब एक विचार नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्मरण पर हुआ है। जैसे-जैसे फास्ट फैशन गति पकड़ रहा है, 2030 तक इसके 50-60 बिलियन डॉलर के बाजार में विकसित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही तेजी से बदलते रस्नानों के कारण टेक्सटाइल अपशिष्ट में भी वृद्धि हो रही है। इसके जवाब में भारत ने एक सर्कुलर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए तेजी से कदम बढ़ाया है। पानीपत अब पी और पोस्ट-कॉन्स्यूमर टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जो टिकाऊ विनिर्माण में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। आज, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुनर्नवीनीकरण फ़ैब्रिक उत्पादक है। यह सालाना 40 बिलियन से अधिक प्लास्टिक की बोतलों को परिवर्तित करता है। 90 प्रतिशत से अधिक पीईटी बोतलों को रीसाइकिल किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है। सतत प्रथाओं को और मजबूत करने के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) सिस्टम और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना के तहत छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह गति व्यापक जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.25 प्रतिशत का योगदान देती है। इसका मूल्य 165.7 बिलियन डॉलर है और आने वाले वर्षों में इसके लगभग दोगुना होने का अनुमान है। इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ वैकल्पिक रेशों का उदय है। रैमी, मिलकवीड, फ्लैक्स, सिसल प्राकृतिक सामग्री हैं जो उच्च प्रदर्शन और जलवायु के अनुकूल दोनों गुणों से भरपूर हैं। मिलकवीड को कभी कृषि खरपतवार माना जाता था, इसे अब हाइ-एंड उपयोग के लिए इन्सुलेशन-ग्रेड वस्त्र में परिष्कृत किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़कर और अनुसंधान निवेश को बढ़ाकर, मोदी सरकार भारत के वस्त्र उद्योग के भविष्य को नया आकार दे रही है। यह ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेगा, स्थिरता में अग्रणी होगा और आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाएगा।

स्थानीय से वैश्विक तक, भारत के हस्तशिल्प का उत्थान

भारत में विरासत अब एक संरक्षित स्मृति नहीं है, यह एक गतिशील आंदोलन है। यह पहचान, सशक्तिकरण और आर्थिक नवीनीकरण का स्रोत बन गया है। यह परिवर्तन हथकरघा क्षेत्र से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। गणतंत्र दिवस पर, ई-वहचान कार्ड के शुभारंभ ने एक नवीन क्रांति को चिह्नित किया है। 35 लाख बुनकरों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री के रूप में शुरू हुआ यह अभियान तब से एक गतिशील आंदोलन में बदल गया है, जिसने 35,000 नए बुनकरों को अपने साथ जोड़ा है। यह समावेश से कहीं अधिक है, यह पुनरुद्धार है। करघे घरों में वापस आ रहे हैं और नई पीढ़ी इसे गर्व के साथ अपना रही है। हस्तशिल्प क्षेत्र में, 30 लाख से अधिक कारीगरों को पहचान कार्ड के तहत पंजीकृत किया गया है, जिससे औपचारिक पहचान और सरकारी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।

2014 से पहले, मुद्रा योजना के माध्यम से सहायता केवल 1.25 लाख बुनकरों तक पहुंचती थी। आज, 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। यह प्रतीकात्मकता से सार्थक सशक्तिकरण की ओर स्पष्ट बदलाव है। करघा अब केवल परंपरा का प्रतीक नहीं रह

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बारिश

से तबाही और भूस्खलन से लोगों की परेशानियां बढ़ी



अजय दीक्षित

उत्तर भारत में विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिलता है और यह प्रतिवर्ष होता है। उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश सड़क, भवन, रास्तों, को भारी नुकसान होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, में उत्तरकाशी, गढ़वाल, टिहरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, मंडी, बिलासपुर, शिमला, नैनीताल, देहरादून आदि जिलों में भीषण तबाही होती है। यह सिलसिला विगत तीस साल से बढ़ा है क्योंकि इन क्षेत्रों में तीस लाख पेड़ विकास के नाम पर दस साल में काटे गए हैं। बेहतासा बढ़ते पर्यटन को देखते हुए इन क्षेत्रों में सरकारों ने सड़कों का निर्माण किया है और व्यवसायियों ने होटलों का निर्माण किया है।

अकेले शिमला, नैनीताल में 2०० होटल है जिनसे पहाड़ों पर वजन बढ़ा है और बारिस के दिनों लैंड स्लाइड्स का खतरा भी हजारों प्रतिशत बढ़ा है। भवनों, बाजारों में अतिक्रमण हो गया है जो पूरे भारत की लाइलाज बीमारी है। पर्वतीय क्षेत्र शोध संस्थान देहरादून के जलवायु शोध कर्ता एस जयशंकर कहते हैं कि पहाड़ों पर हरित क्षेत्रों के चलते यहां भी अधिक रहती है। इसके अलावा तापक्रम भी कम रहता है इस कारण बारिस बहुत और तेज होती है। कुमायूं और गढ़वाल दोनों स्थानों पर औसत बारिश 2000 मिली मीटर के

आसपास है।बारिस के दिनों पानी 3000 मीटर की ऊंचाई से आता है और उसकी गैरिवटी अधिक होती है जो भूस्लखन का कारण बनती है। पहाड़ कच्चे है जियोलॉजी की भाषा में डिसेंट्रिग्रेटेड रॉक है। भवनों, सुरंगों, सड़कों के निर्माण के कारण पहाड़ पोली या दरक गए हैं और पानी के तेज बहाव से गिर जाते हैं। कभी कभी पानी भारी सिल्ट लेकर बहते हैं जैसा पिछली बार ब्यास नदी ने मनाली में तबाही मचाई थी।

पहाड़ों के दूर दर्राज के गांव में लैंड स्लाइड्स नहीं होते हैं क्योंकि वे सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भवन पकाडंडी, पुल बनाते हैं। जिसमें अधिकतर लकड़ी के हल्के होते हैं। लेकिन पूरे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर में हालत इतने खराब नहीं जितने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हैं उसका कारण है कि घाटी में पचास साल से तो विकास नहीं हुआ क्योंकि वहां पर आतंकवाद था पर्यटकों का आना जाना नहीं था। जो घाटी सब भी नहीं हुआ। कश्मीर घाटी में अगर श्रीनगर को छोड़ दें तो वहां सभी मकान लकड़ी के है। पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भूकंप की जद में है। क्योंकि इन क्षेत्रों की टाइटेनिक प्लेट का खिसकने का खतरा बढ़ गया है। अगर कभी भूकंप 8 रेंकेटियर स्केल पर आ गढ़वाल दोनों स्थानों पर औसत बारिश 2000 मिली मीटर के निर्माण से भी खतरा बढ़ गया है।

खास खबर...



रायपुर में टीबी के खिलाफ नई पहल : बीपालएम रेजिम से मरीजों को मिलेगा तेज और प्रभावी इलाज

रायपुर। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन एवं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. अविनाश चतुर्वेदी की उपस्थिति में नोडल डीआरटीबी सेंटर, मेकाहारा, रायपुर में दवा प्रतिरोधक टीबी के मरीजों के लिए एनएम बीपालएम रेजिम का शुरुआत शुरुआत किया गया।

अब तक टीबी के दवा प्रतिरोधी मरीजों को 9 से 18 माह तक पांच से सात दवाएं प्रतिदिन लेनी पड़ती थीं। लेकिन बीपालएम रेजिम के तहत इलाज की अवधि केवल 6 माह रह गई है, और अब केवल 4 आधुनिक दवाओं से इलाज संभव होगा। इन दवाओं की अनुमानित लागत 1 लाख रुपये से अधिक है, जिसे सरकार की ओर से पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी को जड़ से मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर डीआरटीबी वार्ड के समस्त अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

वार्ड 1 में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्यवाई, सीसी रोड और मुख्य मार्ग तोड़कर रोका निर्माण

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल , कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, सहित अन्य सम्बंधित जोन 8 नगर निवेश विभाग अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावकर नगर वार्ड क्रमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत केडिया बिजनेस पार्क के पास अविनाश डेवलपर्स द्वारा बिना विकास अनुज्ञा लिए तथा बिना नगर निगम अनुमति के लगभग 12 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने के उद्देश्य से अवैध सी सी रोड एवं मुख्य रोड का निर्माण किया जा रहा था जिसे जोन क्रमांक 8 नगर निवेश विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से स्थल पर किए जा रहे अवैध सी सी रोड एवं मुख्य रोड को काटने की कार्यवाही करते हुए अवैध अवैध निर्माण पर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी।



करबला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का विधायक ने किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने करबला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। यह कार्य लगभग 2.44 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान विधायक श्री मूणत ने जोन क्रमांक 7 के आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों की निर्देशित किया कि तालाब के चारों ओर परिक्रमा पथ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले बाहरी सीमा पर सरहदी दीवार (बाउंड्री वॉल) का निर्माण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरे परिसर की व्यापक सफाई अभियान चलाकर गंदगी हटाई जाए।

श्री मूणत ने विशेष रूप से कहा

निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों को जोन में नवीन पदस्थापना आदेश जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने निगम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नगर निगम जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी नरेन्द्र नायक को जोन 9 में, जोन 2 सहायक राजस्व अधिकारी स्वाति शुक्ला को जोन 6 में, जोन 3 सहायक राजस्व अधिकारी प्रेमचंद दुबे को जोन 2 में, जोन 4 सहायक राजस्व अधिकारी मानकूराम धीवर को जोन 3 में, जोन 5 सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर अग्रवाल को जोन 10 में, जोन 6 सहायक राजस्व अधिकारी मनीष मरकाम को जोन 1 में, जोन 7 सहायक राजस्व



अधिकारी अमरनाथ साहू को जोन 4 में, जोन 8 सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव को जोन 5 में, जोन 9 सहायक राजस्व अधिकारी विजय शर्मा को जोन 7 में और जोन 10 सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल को जोन 8 में सहायक राजस्व अधिकारी पद पर नवीन पदस्थापना दी है। आयुक्त ने संबंधित सहायक राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया है। आयुक्त ने नगर निगम रायपुर की ओर से उकाशय का प्रशासनिक आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बैठक : सांसद ने स्पोर्ट्स कोटे के पदों पर भर्ती जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने के लिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए एक रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16वें प्राप्ता होता है। राज्य में 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण आम जनता में असंतोष है। उन्होंने रेल अधिकारियों को इन कार्यों में गति लाने और तय समयसीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बन रहे अंडरपास और ओवरब्रिज कार्यों की समीक्षा कर, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूर्ण किया जाए। साथ ही, नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्व स्थानीय सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव लेने की आवश्यकता बताई। उन्होंने दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि और इसके नागपुर तक विस्तार, रीवा-बिलासपुर ट्रेन को रायपुर-दुर्ग तक विस्तारित करने और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश



दिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने रेलवे ट्रैक के आसपास पौधारोपण की कार्ययोजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने की बात कही। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और देवभोग और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल स्थापित करने के निर्देश दिए। जिससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बैठक में रावघाट-धमतरी कनेक्टिविटी, औद्योगिक कारिडोर की प्रगति, रायपुर-अभनपुर रेल लाइन के धमतरी तक विस्तार, परमालकसा-खरसिया प्रस्तावित रेल लाइन के तहत आने वाले गांवों में जमीन की खरीदी-

बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने के निर्देश दिए इस प्रतिबंधों के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है वहीं रावघाट में रेल लाइन के प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी देने जैसे प्रमुख मुद्दे भी उठाए गए। बैठक में ट्रेनों के ठहराव, नई ट्रेनों के संचालन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने, कुली, वेंडर और हम्मालों को सुविधाएं देने जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सांसद श्री अग्रवाल ने ट्रेनों के निरस्तीकरण और लेटलतीफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने, स्टेशनों के उन्नयन (अमृत स्टेशन योजना), आरक्षण कोटा बढ़ाने उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर रायपुर से पुरी तक वंदे भारत ट्रेन और छत्तीसगढ़ से रत्नागिरी व गोवा तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग करने की बात कही।

बिलासपुर से नाथद्वारा (राजस्थान) सीधी

ट्रेन चलाने, रायपुर से जोधपुर (भगत की कोठी) को सप्ताह में पांच दिन चलाने, मध्य रेल मंडल नागपुर एवं रेल जोन कार्यालय मुंबई से संचालित ट्रेन 12105-12106 विदर्भ एक्सप्रेस (मुंबई गोविंद्या), 12114- 12135 (नागपुर- पुणे, पुणु नागपुर एक्सप्रेस) 11040-11039 पूर्ण- भंडारा, भंडारा ङ्क पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रायपुर / बिलासपुर तक विस्तारित करने, बिलासपुर से चलने वाली ट्रेनों बिलासपुर-चेन्नई (12851-52), साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर- हापा (22939-40)। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20825-826) एवं बिलासपुर नई दिल्ली (12441-42) का भाटापारा में स्टॉपेज दिए जाने, पुरी-दुर्ग (18425-18426) और संबलपुर-नांदेड (18309-18310) के संतला (एसएफसी) रेलवे स्टेशन पर विस्तार, दुर्ग-नौतवा एक्सप्रेस, 18201 को सप्ताह में पांच दिन चलाने, गोविंदा जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को रायपुर तक चलाने, कोरोना काल के समय से बंद ट्रेन स्टॉपेज पुनः बहाल करने, 18258 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस एवं इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्टॉपेज शुरू करने के निर्देश दिए।

साथ ही तिल्दा-नेवरा के दैनिक रेल

यात्रियों की समस्या के निवारण, आरंग रेल्वे स्टेशन पर कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, दुर्ग-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस, हजयत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम (समता एक्सप्रेस का स्टॉपेज एवं टिकट आरक्षण केन्द्र स्थापित करने, अभनपुर मेन मार्केट में निर्माणधीन ब्रॉडगेज में नेशनल हाइवे के क्रॉसिंग में सी आकार व नया अंडरब्रिज बनाये जाने, नगर पालिका परिषद अभनपुर में बस स्टैंड स्थित रेल्वे अण्डर ब्रिज के पास फाटक लगवाने, रेल टिकट आरक्षण केन्द्र खोलने, बरबंद रेल्वे फाटक से बरबंद रेल्वे अंडरब्रिज तक कच्ची सड़क को पक्की करने, उरकुरा फाटक में अंडरब्रिज ओवरब्रिज निर्माण, रायपुर से अभनपुर और अभनपुर से रायपुर चल रही लोकल मेमू' नई ट्रेन का स्टॉपेज जोरा (रायपुर) में करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए कहा है तथा रेल मंडल में रिक स्पोर्ट्स कोटे के सभी पदों को भरने और राष्ट्रीय खिलाड़ी मीना साहू अनियमित कर्मचारी को नियमित करने हेतु उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बैठक में सांसद विजय बघेल, सांसद भीजराज नाग, सांसद महेश कश्यप, सांसद रूपकुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन सहित रेलवे के मुख्य महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम रायपुर दयानंद, प्रधान मुख्य अभियंता मुदित भटनागर, राहुल अग्रवाल, आलोक तिवारी एवं IG RPF मुनव्वर खुरशीद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसंपर्क विभाग के उपसंचालक आनंद प्रकाश को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जनसंपर्क विभाग में 31 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले उप संचालक आनंद प्रकाश सोलंकी को सेवानिवृत्ति अवसर पर 30 जून सोमवार को जनसंपर्क संचालनालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में अपर संचालक जे एल दरियो, अपर संचालक उमेश मिश्रा एवं अपर संचालक संजीव तिवारी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री सोलंकी की सेवा, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और योगदान को याद करते हुए उन्हें

भावभीनी विदाई दी। उल्लेखनीय है कि आनंद प्रकाश सोलंकी ने अपने सेवाकाल के 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए राज्य शासन की योजनाओं एवं नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनके कार्यकुशलता, निष्ठा और विश्वास का प्रमाण है। विभागीय अधिकारियों ने इस अवसर पर श्री सोलंकी के उज्ज्वल भविष्य और सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना की। अपर संचालक उमेश मिश्रा एवं संयुक्त संचालक बी.एम तंबोली ने कहा कि श्री सोलंकी का सरल व्यवहार, उनकी सौम्यता और कार्यशीली अनुकरणीय है।

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है-सिन्हा

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर द्वारा आज नव नियुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के लिए प्रथम चरण के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम (3 माह) का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जून, 2025 से 27 सितम्बर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुख्य न्यायाधीश ने अपने प्रभावशाली संबोधन में नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक

सेवा में चयनित होने पर बधाई दी एवं ध्यान आकर्षित किया कि, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है। विधि के शासन को बनाए रखने एवं सामान्य नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह पवित्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उन्होंने सतत अध्ययन, न्यायिक आचार संहिता एवं विनम्रता के महत्व को

रेखांकित किया, एवं नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से जुड़ने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान रखी गई नींव उनके भविष्य के न्यायिक आचरण एवं क्षमता को आकार देगी।

मुख्य न्यायाधीश ने समय की पाबंदी, तैयारी और धैर्य को एक अच्छे न्यायाधीश की पहचान बताया, साथ ही

स्मरण कराया कि विलंबित न्याय, अन्याय के समान है और कभी-कभी, जल्दबाजी में किया गया न्याय भी अन्याय ही होता है। इसलिए गति और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब आप न्याय के संरक्षक हैं, उस स्तर पर जहाँ सामान्य नागरिक न्याय प्रणाली से पहली बार जुड़ता है। यहाँ, निचली अदालतों में, न्याय की सच्ची छवि जनता के मन में बनती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायिक सेवा की यह यात्रा निरंतर अध्ययन, निर्भीक स्वतंत्रता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण होगी। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री एवं न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण की भी उपस्थिति रही निर्माण में पत्रकारिता की जिम्मेदार भूमिका को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया।

आटोमैटिक हुई रायपुर एयरपोर्ट की पार्किंग: आए दिन होने वाले विवादों पर लगेगा विराम, स्वचालित मशीन से निकलेगी पर्ची

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पार्किंग की पर्ची को लेकर होने वाले विवाद पर अब विराम लगने की संभावना है। वसूली की विभिन्न शिकायतों के बाद विमानतल प्रबंधन ने आटोमैटिक पार्किंग सिस्टम विकसित कर इसे प्रारंभ कर दिया है। अब स्वचालित मशीन के जरिए वाहन की पर्ची निकलेगी और विमानतल से वाहन के एग्जिट होने के दौरान फास्ट टैग के जरिए शुल्क कट जाएगा। विमानतल पर यात्रियों को छोड़ने वाली गाड़ियों के शुल्क को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती थी और वाहन चालकों के साथ ठेका कर्मियों के बीच मारपीट तक हो जाती थी। इसे लेकर अक्सर आवाजाही करने वाले यात्रियों में दहशत की स्थिति बनी रहती थी। पार्किंग के नाम पर अधिक वसूली की शिकायत आए दिन प्रबंधन पर पड़ चुकी थी। इन विवादों पर अब लगाम लगने की संभावना है।



विमानतल प्रबंधन ने पार्किंग सिस्टम को ईसानी दखल से दूर रखते हुए आटोमैटिक सिस्टम तैयार कर इसे शनिवार से लागू भी कर दिया है। इस सिस्टम से पार्किंग एंट्री पर स्वचालित सिस्टम से पर्ची निकलेगी, जिसे सभी वाहन चालक स्वयं ले सकेंगे। एंट्री पर लगे सिस्टम की सहायता से वाहन का नंबर और एंट्री का समय पर्ची पर स्वतः ऑटिक

होगा और पर्ची लेने के बाद पार्किंग एंट्री पर लगा बेरियर खुल जाएगा।

इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों की सुविधा और समय की बचत होगी। पर्ची और शुल्क प्राप्त करने के लिए उन्हें अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों के वाहन से झूठे और पिकअप समय की तयशुदा दर के अनुसार पैसा कटेगा। वाहन चालक अपने मित्र या रिश्तेदार को एयरपोर्ट पर झूठे करने के बाद जब पार्किंग एग्जिट पर पहुंचेंगे तो फास्टेज से पैसा अपने आप टोल बूथ की तर्ज पर कट जाएगा।

एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहनों से लिए जाने वाले पार्किंग शुल्क के सिस्टम में ही बदलाव किया गया है। इसका पार्किंग की दरों से संबंध नहीं है। शुल्क दरों का निर्धारण आठ बजे से पहले किया गया था। कारों के लिए आठ घंटे का शुल्क 40 रुपये तय किया गया है। प्रीमियम कारों के लिए यह शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

आयुक्त ने अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर में उपायुक्त एके हालदार को नगरीय निकाय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल सामान्य सभा सभागार में बुके, श्रीफल, शाल, स्मृतिचिन्ह प्रदत्त कर रायपुर नगर निगम में जोन कमिश्नर और निगम उपायुक्त के पद पर निवृत्त 6 वर्ष तक सेवाएं देने हेतु सम्मानित किया और उन्हें सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने रायपुर नगर निगम में उपायुक्त एके हालदार द्वारा लगातार 6 वर्ष सेवाएं देने को सराहा व कहा कि उनकी स्पष्टवादिता सराहनीय रही है। सभापति ने उनके उज्ज्वल भविष्य, स्वस्थ सुखी जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

सभापति ने आयुक्त से अनुरोध किया कि नगर निगम रायपुर के सेवानिवृत्त होने वाले निगम अधिकारियों व कर्मचारियों का



सेवानिवृत्ति दिवस पर नगर निगम की ओर से सेवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके स्वत्वों का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए। आयुक्त विश्वदीप ने एके हालदार द्वारा नगर निगम की सेवा निष्ठा, लगन, कड़ी मेहनत से करके अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने को सराहा। उन्होंने उनके सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी, उज्ज्वल जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दीं। आयुक्त ने प्रभारी अपर आयुक्त सामान्य प्रशासन कृष्णा खटीक को सेवानिवृत्ति दिवस पर निगम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम मुख्यालय में रखा जाना एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान

किया जाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

सेवानिवृत्त उपायुक्त एके हालदार ने प्रशासनिक सेवाकाल स्वच्छता निरीक्षक के रूप में प्रारंभ किया एवं अपने कार्यों से पदोन्नति पाकर वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

जोन कमिश्नर, उपायुक्त एवं निगम आयुक्त के पदो पर सेवारत रहे. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से नगरीय निकाय की सेवा निष्ठा और ईमानदारी से करने का प्रण लेने का अनुरोध किया। अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, यूएस अग्रवाल, विनोद पाण्डेय, कृष्णा खटीक, जोन कमिश्नर अरूण ध्रुव ने एके हालदार के सेवाकाल को सराहते हुए उनके संबंध में संस्मरण सुनाए कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर सभी जोन कमिश्नर, उपायुक्तगण, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, निगम अधिकारी, कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

आरना इंटरप्राइजेस

कांदावाला

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक

सकुल्लर मार्केट केम्प-2, भिलाई
न्यू जेपी स्पोर्ट्स के सामने
7828844440, 9993045122

नया बस स्टैंड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

GST NO. 22AHMPB9621P122
PH: 07488-4060131

अनुप ट्रेडर्स
ऑटोफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

कला को सम्मान और कारीगरों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पारंपरिक रूप से बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और माटी कला से जुड़े कारीगरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य में लगे लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित करना और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य में रेशम, हस्तशिल्प, खादी, हथकरघा और माटीकला से जुड़े पारंपरिक कारीगरों, बुनकरों और उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की



गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल सभी घटकों से जुड़ी आधारभूत जानकारी ली और कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और विपणन के लिए ठोस एवं समन्वित

कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि स्थायी रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रेशम उत्पादन, कोसा वस्त्र निर्माण और हथकरघा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की परंपरा और दक्षता को नई ऊंचाई देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री

साय ने कहा कि प्रदेश में संचालित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कुशल कारीगरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने संस्थान के सुचारु संचालन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की बात कही। साय ने कहा कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, उसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक शिल्प और बुनाई से जुड़े अत्यंत कुशल कारीगर मौजूद हैं, जो पीढ़ियों से बेहद सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां एवं उत्पाद तैयार करते आ रहे हैं। ये हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि इन उत्पादों को राज्य और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर

बिक्री और निर्यात की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने की बात भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिटी मॉल का निर्माण समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य के उत्पादों को विशेष स्थान और ब्रांडिंग मिल सके तथा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, ताकि रेशम उद्योग को मजबूती मिले और अधिक से अधिक लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हम अपने पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों की कला को सम्मान देकर ही उनके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।

भूजल संरक्षण की दिशा में सरगुजा जिला प्रशासन की नई पहल



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सरगुजा जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बोरवेल सैंड रिचार्ज फिल्टर योजना की शुरुआत की गई है। इस नवाचार के माध्यम से वर्षा जल को बर्बाद होने से बचाकर सीधे भूजल भंडारण में पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर विलास भोसकर के नेतृत्व में सभी शासकीय भवनों, स्कूलों, पंचायत परिसरों और सार्वजनिक स्थलों में ड्राई बोरवेल में बोरवेल सैंड रिचार्ज फिल्टर लगाए जा रहे हैं।

यह विशेष फिल्टर रेत, चारकोल और गिट्टी की परतों से बना होता है, जो बारिश के पानी को शुद्ध कर भूमिगत जलस्रोतों में प्रतिक्रिया करता है। इससे न केवल जलस्रोतों का पुनर्भरण होगा, बल्कि बोरवेल की आयु और क्षमता भी बढ़ेगी। जिले में बारिश के पानी का अधिकतम उपयोग कर जल संकट को दूर करने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे जिले में जल संवर्धन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर को सुधारने के लिए सभी विभागों और आमजन की सक्रिय भागीदारी से वर्षा जल का हर बूंद संरक्षित कर भू-जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

खनिज आधारित उद्योगों से राज्य के विकास को मिलेगी नई गति: पी. दयानंद

200 मिलियन टन से अधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की नीलामी के लिए प्री-बिड सम्मेलन में शामिल हुए निवेशक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज के नए ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में आज नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों के लिए प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करना है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि हमें नई औद्योगिक नीति के अनुरूप खनिज क्षेत्र के विकास के साथ 'विकसित भारत,



विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज नीति और नई उद्योग नीति से खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।

खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह

भवन में एक ड्रिल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, ताकि अन्वेषण की गुणवत्ता और सटीकता को सुदृढ़ किया जा सके।

खनिज सचिव दयानंद ने यह भी बताया कि डीजीएम द्वारा चयनित कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है, जिनमें 4 चूना पत्थर, 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में उपलब्ध संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से अधिक भंडार बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित हैं, जिनमें औसतन 42 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आंकी गई है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे इन ब्लॉकों को एक आकर्षक औद्योगिक अवसर के रूप में देखें और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग, पारदर्शिता और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के

लिए प्रतिबद्ध है।

खनिज विभाग के संचालक श्री रजत बंसल ने ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निविदा पोर्टल पर सभी खनिज ब्लॉकों से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्रों में रेलवे और सड़क जैसे मजबूत आधारभूत ढांचे के साथ स्थानीय श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उद्योगों की स्थापना सुगम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। प्रति वर्ष 3-4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की स्थापना की संभावना के साथ इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक अमित भारवाड़कर, संयुक्त संचालक अनुराग दीवान, संजय कनकाने सहित विभिन्न निवेशक, औद्योगिक प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तथा खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पीएम सूर्य घर योजना से रवींद्र सिंह को मिली राहत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केन्द्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। यह योजना बिजली के साथ आर्थिक बचत और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए लाभदायक है। हर घर को ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

सूरजपुर जिला निवासी रवींद्र सिंह ने इस योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाया है। श्री सिंह ने इस योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर



ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद डिस्कॉम से पंजीकृत वेंडर द्वारा उनके घर में सोलर यूनिट लगाई गई। उन्होंने बताया कि उनके घर में पहले प्रतिदिन 12 से 13

यूनिट बिजली की खपत होती थी, लेकिन अब उनके घर में स्थापित सोलर सिस्टम से रोजाना 17 से 19 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस कारण अब उनका बिजली बिल शून्य नहीं बल्कि माइनस में आ रहा है और हर महीने ऊर्जा क्रेडिट भी मिल रहा है, जो भविष्य के बिल में समायोजित होता है।

रवींद्र सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना ने हमें न सिर्फ बिजली बिल से मुक्ति दिलाई, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी हमारा योगदान बढ़ाया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस योजना का लाभ ले और आत्मनिर्भर बनें।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: पर्यावरण संरक्षण की ओर एक सशक्त कदम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज देश के आम नागरिकों के लिए न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी सशक्त माध्यम बन रही है। इस योजना के अंतर्गत आमजन को रियायती दरों पर घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे वे खुद की बिजली जरूरतें पूरी कर सकें और बिजली बिलों से राहत पा सकें।

कोरबा जिले के कटघोरा निवासी गोरे सिंह राजपूत ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। पहले जहां हर माह उन्हें ढाई से तीन हजार बिजली बिल चुकानी पड़ती थी, वहीं अब



मासिक बिजली बिल लगभग शून्य है। योजना का लाभ लेकर श्री राजपूत अपनी घरेलू विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली पैदा कर रहे हैं, साथ ही बिजली बिल के भुगतान की राशि की बचत कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि बिजली जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में

अपनी अहम योगदान दे रहे हैं। यह पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक नई सोच की शुरुआत है, बिजली बनाओ, बचत बढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ। हितग्राही राजपूत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत घर पर सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया। परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के बेहतर विकल्प एवं हरित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा को अपनाने का निश्चय किया। सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी लाभदायक है। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता न ही प्रकृति को हानि नहीं पहुंचता है।

हितग्राही राजपूत ने योजना से हो रहे लाभ के बारे में बताया कि सोलर पैनल

लगवाने के बाद से उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। यह योजना भेरे जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हर माह की बचत से भविष्य की योजनाओं को साकार करना भी संभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व उनके द्वारा योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया गया था, कुछ ही दिनों में विभागीय स्वीकृति के बाद उनके छत पर 1.95 लाख रुपये का बिजली से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। लाभार्थी श्री गोरेसिंह राजपूत की इस पहल से न सिर्फ उनका जीवन आसान हुआ है, बल्कि यह प्रेरणा बन गई है।

पीएम सूर्य घर योजना से ओमप्रकाश उपाध्याय को बिजली बिल से मिली आजादी

रायपुर। केन्द्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' से अब आम लोग स्वयं के घर में बिजली बनाकर न केवल बिजली बिल से मुक्ति पा रहे हैं, बल्कि हर महीने बिजली विभाग से अतिरिक्त यूनिट के बदले लाभ भी कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम परिवार बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हर महीने की बचत से आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं।

इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के सतपता, विश्रामपुर निवासी ओमप्रकाश उपाध्याय भी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। श्री उपाध्याय ने 7 मार्च 2025 को योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद डिस्कॉम से पंजीकृत वेंडर द्वारा उनका सोलर सिस्टम स्थापित किया गया।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में

JITU'Z

CUT N SHINE

93009-11331

रंगोली वेग्लस के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्गा (छ.ग.)

CAR DECOR

House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

SAIRAM

Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES

FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के अग्रगण्य के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्टेक्स एवं ग्रहवाल उपलब्ध यहां
उचित व्याज दर पर ग्रिस्वी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

युवती ने की खुदकुशी

दंतेवाड़ा। जिले में एक युवती ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। पाइप पर गमछा का फंदा बनाया और झूल गई। फिलहाल सुसाइड का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, मृत युवती का नाम श्यामबती कड़ती (23) है। ये दंतेवाड़ा के कुम्हाररास को रहने वाली थी। मजदूरी का काम करती थी। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले शाम 6 बजे काम कर लौटी थी। रात में परिजनों के साथ खाना खाई।

फिर अपने कमरे में सोने चले गई थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं सुबह यह जल्दी नहीं उठी। जिसके बाद परिजनों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई भी रिस्रॉन्स नहीं मिला तो दरवाजा को तोड़ा गया। जब परिजन अंदर गए तो उन्होंने फंदे से लटकती अपनी बेटी की लाश देखी। रोने और शोरगुल की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी घर पहुंच गए। वहीं इस मामले की जानकारी सीट कोतवाली पुलिस को भी दी गई। मौके पर जवान पहुंचे।

बलरामपुर में भारी बारिश, नाले में उफान बहे मां-बेटे की मौत

बलरामपुर। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में उफनते नाले को पार कर रहे मां-बेटे बह गए। दोनों का शव मंगलवार को बरामद हुआ है। आमगांव निवासी विशुन (20) को पत्नी रजनी पहाड़ी कोरवा (40) अपने 2 वर्षीय बेटे आनंद के साथ मायके रकैया गांव गई थी। बताया जा रहा है कि वहां से शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच वह बेटे को लेकर पैदल ही लौट रही थी। दोनों गांव के बीच स्थित बढ़नी झरिया नाले में कमर तक पानी भरा था। बेटे को गोद में लेकर रजनी कोरवा नाला पार कर रही थी, तभी दोनों नाले के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने मां-बेटे का शव घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में पड़ा देखा। सूचना शंकरगढ़ पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एक प्रेमी ने प्रेमिका का गुस्सा एक दूसरे लड़के पर उतारा

भिलाई। प्रेमिका से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर एक अन्य युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। यह सनसनीखेज घटना भिलाई के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है। सू्यों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी साहिल सोना अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर नाराज था। गुस्से में आकर उसने बदला लेने की नीयत से अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर नीरज वर्मा नामक युवक को निशाना बनाया। दोनों ने नीरज पर पहले हाथ-मुर्कों से हमला किया और फिर चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल नीरज को सुपेला स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित युवक के पिता अजय वर्मा ने पुरानी भिलाई थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नीरज द्वारा दिए गए हुलिए के आधार पर आरोपी साहिल सोना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस नाबालिग सहयोगी की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है।

जशपुर पुलिस ने पकड़े बकरी चोर, कार से पहुंचते थे शातिर, चर रही बकरियां उठा ले जाते थे बादमाश

श्रीकंचनपथ न्यूज

चर रही बकरियां उठा ले जाते थे बादमाश
जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने बकरी चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में तीन चोर व एक खरोदरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की बकरियां व कार बरामद किया गया है। यह चोर इतने शातिर हैं कि चर रही बकरियों को कार से उठाकर ले जाते और सस्ते दाम में कसाई को बेच देते। मामला जशपुर के बागीचा थाना क्षेत्र का है।

दरअसल इस मामले में 30 जून को को ग्राम कुहापानी थाना बागीचा निवासी प्रार्थी सुरेश तिग्गा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि 29 जून को वह ग्राम कुहापानी में अपने घर से कुछ दूरी पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। बकरियों से कुछ दूरी पर सड़क के पास खड़ा था कि इसी दौरान करीबन 3.00 बजे सकी बकरियों के पास अचानक एक ग्रे कलर की एक कार आकर रुकी, जिसमें से पांच व्यक्ति उतरे व उसकी दो नग बकरी व खस्सी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में पिछले माह हुई एक चोरी के मामले में बिलासपुर का हिस्ट्रीशीटर अपने साथियों के साथ पकड़ाया है। बदमाश ने लोहे के रॉड से घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। इस मामले में पुलिस ने एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात व घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल कुल कीमती 7 लाख 36 हजार रुपए बरामद किया है। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा है।

इस मामले में 19 मई 2025 को कबीर नगर अमलेश्वर निवासी मुकेश देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि 18 मई को घर का दरवाजा बंद कर परिवार सहित ससुराल चंगौरभाटा गया था। दूसरे दिन सुबह वापस लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर आदि कीमती लगभग 1लाख 90 हजार रुपए कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अमलेश्वर में धारा 331

डिलीवरी ब्वाँय वाले को बंधक बनाकर पीटा, चार युवकों पर अपराध दर्ज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। जिले में डिलीवरी ब्वाँय को दो युवकों ने बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। युवक पार्सल छोड़ने गए थे। तभी पार्सल के रुपए मांगने की बात पर उन्हें 4 लोगों ने मिलकर कमरे में बंद कर बेल्ट और लकड़ी से पीटा। उनके पास रखे कैश, मोबाइल और बाइक को लूट लिया। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक गमेकेला का रहने वाला सावन पैंकरा (21) और उसका दोस्त नित्यानंद एक प्राइवेट डिलीवरी फर्म में पार्सल छोड़ने का काम करते हैं।

बुधवार को दोनों दोस्त इन्द्रानगर में रहने वाले सुमन सारथी को पार्सल छोड़ने के लिए गए थे। उनका दो पार्सल था। ऐसे में सुमन को पार्सल देने पर उसने एक पार्सल का रुपए दिया और दूसरे पार्सल का रुपए कुछ देर में आकर ले जाने बोला तब सावन और नित्या वहां से चले गए और शाम को उसके पास फिर से रुपए लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद विक्रों सारथी

गुस्सा हो गया। रुपए कल लेना कहने लगा। ऐसे में सावन ने उसे बताया कि पार्सल का रुपए ऑफिस में जमा करना होता है। जिससे विक्रों नाराज हो गया और उनके साथ मारपीट करने लगा। तब विक्रों के तीन अन्य साथी आ गए और कमरे में ले जाकर बेल्ट व लकड़ी से चारों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया।

इसके बाद उनके पास रखे डिलीवरी का 5 हजार रुपए, दो मोबाइल, बाइक को लूट लिया और करीब एक घंटे बाद उन्हें वहां से भगा दिया। मारपीट से सावन पैंकरा और नित्यानंद के हाथ, पैर में चोट पहुंची। घटना के बाद डर के कारण दोनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन उन्होंने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी। ऐसे में परिजनों के कहने पर सोमवार को सावन पैंकरा लैलूंगा थाने पहुंचा और मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां पुलिस ने विक्रों समेत उसके 3 साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

राजनांदागांव में गोलीकांडः आरोपी एमपी में पकड़ाया

राजनादागांव। अवैध रेत खनन में गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा उर्फ गोली गुर्जर को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर के राजनांदागांव लेकर आई है। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन और परिवहन पर बेअसर कार्रवाई के बीच माफियाओं ने गोलीकांड को अंजाम दिया। घटना 11 जून की रात करीब 7 से 7:30 बजे के बीच की है, जब गांव मोहड़ नदी के किनारे अवैध रेत निकासी के लिए जेसीबी से रेम बनाया जा रहा था। इसका विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने हमला

कर दिया और गोलियां चला दी। इस फायरिंग में रोशन मंडावी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके गले को छूते हुए निकल गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य दो ग्रामीण जितेन्द्र साहू और ओम प्रकाश साहू भी घायल हुए। घटना के बाद बसंतपुर थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित आर्म्स एक्ट और माइनिंग एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। मामले में पुलिस अधीक्षक मोहित गंग के निर्देशन पर संयुक्त 5 टीम टीम गठित की गई। लगातार आरोपियों की अलग-अलग टिकाने उतर प्रदेश झाँसी, नागपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना आदि जगहों में दबिश दे रही थी।

श्रीकंचनपथ न्यूज

खैरागढ़। नगर पालिका कार्यालय के सामने मंगलवार शाम एक चालान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यातायात नियम उल्लंघन पर स्कूटी सवार युवती का चालान काटे जाने से नाराज उसका भाई शशांक ताप्रकार बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। युवक और पुलिसकर्मियों के बीच बहस और नोकझोंक हुई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।

पुलिस के अनुसार, हेलमेट और दस्तावेज जांच के दौरान स्कूटी सवार युवती के पास जरूरी कागजात अथुर्े पाए गए थे, जिसके बाद चालान काटा गया।



रिश्तेदार के यहां छुपाया था चोरी का सामान

प्राप्त जानकारी के आधार पर टीम को बिलासपुर भेजा गया। जहां रिशेश पाण्डे एवं सोहन पटेल को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 18 मई की रात को वह अपने साथी लक्की यादव, तोरवा बिलासपुर के साथ अमलेश्वर के उक्त मकान का ताला तोड़कर चोरी की। चोरी का सामान संतोषी गोस्वामी के माध्यम से सिरगिट्टी निवासी सुखनंदन सोनी बेचे दिया। कुछ सामान रिशेश अपने पिता विनय पाण्डे और सोहन पटेल ने अपने रिश्तेदार रमेश पटेल को छिपाने के लिए दिया। आरोपियों की निशानदेही पर सोने के जेवर 51 ग्राम, 430 मिग्रा कीमती 3 लाख 56 हजार, चांदी के जेवर 466 ग्राम कीमती 2 लाख 30 हजार एवं बुलेट मोटर सायकल 1 लाख 50 हजार कुल कीमती 7 लाख 36 हजार का मशरुका जब्त किया गया।

डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1.252 किलोग्राम डोडा, नगदी 1.90 लाख रुपये, तौल मशीन, कार, एंक्टिवा और मोबाइल फोन सहित कुल 4.50 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जो रायपुर में धुम-धुमकर डोडा की बिक्री कर रहा था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एंटी फ्राइम एंड साइबर यूनिट तथा आमानाका थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखाबिर की सूचना पर हीरापुर टाटीबंध स्थित छठ तालाब सूर्य मंदिर के पास एक कार को घेराबंदी कर रोका। कार में सवार व्यक्ति की पहचान ओमप्रकाश शर्मा उर्फ पप्पू (53 वर्ष), निवासी ग्राम रोजा, जिला



झालावाड़, राजस्थान के रूप में हुई। तलाशी में कार से डोडा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यह मादक पदार्थ राजस्थान से लाकर रायपुर में एंक्टिवा और कार के जरिए खपतकर्ताओं तक पहुंचाता था। उसके पास मादक पदार्थ परिवहन व बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

जब्त सामग्री में डोडा –1.252 किलोग्राम नगद रकम –1,90,540 तौल मशीन कार क्रमांक RJ17

CA 8552 एंक्टिवा CG07 AE 5469 मोबाइल फोन पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 216/25 धारा 15 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक के आधार पर अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एएसपी (पश्चिम) डीआर पोर्ते, एएसपी (फ्राइम) संदीप मि्तल, सीएसपी

अमन कुमार झा, डीएसपी संजय सिंह, निरीक्षक सुनील दास और प्रभारी निरीक्षक परेश पांडेय के मार्गदर्शन में किया गया। टीम में शामिल अधिकारी में राजेन्द्र कंवर, फूलचंद भगत, वीरेंद्र भार्गव, जसवंत सोनी, मार्टंड सिंह, मुनीर राजा, लक्ष्मीनारायण साहू, हरजीत सिंह, अजय चौधरी, किसलय मिश्रा, विकास शर्मा, श्याम थावरे, दीपक पांडेय, आशीष शुक्ला और गुलशन चौबे शामिल हैं।

बाथरूम लगने का बहाना कर बाल अपराधी भागे

कोरबा। बाल संरक्षण गृह से दो किशोर फरार हो गए। यह घटना 30 जून की सुबह 4 बजे की है। दोनों किशोर बाथरूम जाने के बहाने कमरे से निकले और रोशनदान की जाली तोड़कर भाग गए। फरार हुए किशोरों में एक 17 वर्षीय है, जिसे पॉक्सो और छेड़छाड़ के मामले में 16 जून को निरुद्ध किया गया था। दूसरा 16 वर्षीय किशोर चोरी और हिंमतर्ष के मामले में 19 जून से यहां था। एक किशोर जांजगीर-चांपा जिले का और दूसरा कोरबा पुलिस चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। जांजगीर में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। वह पहले भी 5–6 बार यहां आ चुका है और एक बार रिसदी के संरक्षण गृह से भाग चुका है। बाल संरक्षण गृह को लाल ही में बालको थाना के सामने स्थित नए भवन में स्थानांतरित किया गया था।

बहन की स्कूटी का चालान कटा, नाराज युवक बैठा धरने पर



चालान की जानकारी मिलने पर युवती का भाई मौके पर पहुंचा और पुलिस से बहस करने लगा। उसका आरोप था कि चालान के दौरान पुलिसकर्मियों ने उसकी बहन से गलत तरीके से बातचीत की और

बदसलूकी की। इसी बात से नाराज युवक सड़क पर बैठ गया और कार्रवाई रोकने की मांग करता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक का यह धरना चालान रद्द करवाने

का दबाव बनाने के इरादे से किया गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें युवक पुलिसकर्मियों से बहस करता और बीच सड़क पर नारेबाजी करते हुए बैठा नजर आ रहा है। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों के समझाने और पुलिस द्वारा जांच का आश्वासन देने के बाद युवक ने धरना समाप्त कर दिया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर इलाके में चर्चा है कि क्या ट्रैफिक चालान जैसी कार्रवाई के विरोध में इस तरह सार्वजनिक सड़क पर धरना देना उचित है?

एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की

मामले में आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक संत लाल आयाम, थाना प्रभारी मणिपुर (जिला अंबिकापुर) निरीक्षक अश्विनी सिंह व उनकी टीम, सहायक उप निरीक्षक बैजन्ती किंठो, नरेन्द्र मिंज, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह, आरक्षक मुकेश पांडे, बक्की रवि व सुनील मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी बगीचा के द्वारा त्वरित गति व सुझबुझ से, अंबिकापुर पुलिस की सहयोग से आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, बाकी फ़रार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी ने कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है।

को कोशिश की लेकिन पुलिस के मनोवैज्ञानिक पृष्ठताछ के आगे वह टूट गया और बताया कि उसके द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर कार से बकरी को चुराकर ले जाया गया था। चोरी की बकरी को सीतापुर निवासी नूअल्ल खान के पास बेच देना बताया। पुलिस के द्वारा आरोपी अजीत पैंकरा की निशानदेही पर मामले में शामिल दो आरोपी आशीष केरकेट्टा (20) निवासी तिलाईधार थाना सीतापुर जिला अंबिकापुर, अंकित तिग्गा

(20) निवासी तिलाईधार थाना सीतापुर जिला अंबिकापुर व चोरी की बकरी खरीदने वाले आरोपी नूअल्ल खान (42) निवासी रायकरा थाना सीतापुर जिला अंबिकापुर को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से दो नग चोरी की बकरी को भी बरामद कर लिया गया है। साथ बकरी चोरी में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा चर्चित कर लिया गया है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान

निखार बैंगल

मो.- 9826186026

Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

Ashok JEWELLERY

Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sia Jewellery

Beside Parakh Jewellers,
Akash Ganga,
Supela, Bhilai

Hello: 0788-4052727

Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

राकेश ट्रेडर्स

राकेश ट्रेडर्स जो सर्व के पास था वह आगे चला गया है पिछले दस वर्षों से

Dealers

Marbles, Grinight, Black Stone,
Nano & Double Charge
Verified Tiles Digital Wall &
Floor Tiles Cement Colour etc.

रायपुर २२२ पर माल उपलब्ध है

Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357

Krishna Talkies Road, Beside Swami Aatmanad School, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि

128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ इज ऑफ इडिंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य

► मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ

► 1 लाख 23 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त : 20 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

► लॉजिस्टिक नीति एवं जन विश्वास विधेयक से छत्तीसगढ़ में विकास को मिलेगी नई गति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 के शुभारम्भ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। हम अपने राज्य को नक्सल प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब बना रहे हैं। यह प्रदेश अब निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एक दिन पूर्व ही आयोजित केबिनेट की बैठक में हमने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देश की कनेक्टिविटी का केंद्र बिंदु है। यह नीति

भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है छत्तीसगढ़ - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय



लॉजिस्टिक सेक्टर और ई-कॉमर्स में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेंगी, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। लॉजिस्टिक नीति से राज्य में ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग, व्यापार और किसानों को आधुनिक, सस्ती भंडारण और वितरण सुविधा प्राप्त होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी के माध्यम से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय और नागरिक जीवन में अनावश्यक जटिलताएं दूर होंगी। कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने से व्यवसायियों को बेवजह न्यायालयीन प्रकरणों में फंसे से राहत मिलेगी और न्यायिक खर्च में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार व जीवनयापन में सहजता सुनिश्चित की जाएगी। ईज ऑफ इडिंग बिजनेस में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि निवेशकों, उद्योगपतियों और नागरिकों के लिए ऐसा परिवेश बने जिसमें न्यूनतम बाधाएं हों और विकास के हर क्षेत्र में अधिकतम संभावनाएं खुलें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिनसे ईज ऑफ इडिंग बिजनेस और स्पीड ऑफ इडिंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रदेश में निवेश का वातावरण इतना सशक्त हुआ कि सिर्फ छह महीनों में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में आयोजित इवेस्टर्स समिट से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। दिल्ली समिट में 15,184 करोड़ रूप, मुंबई में 6,000 करोड़ रूप और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में वृहद निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में 1,63,749 करोड़ रूप का निवेश आकर्षित किया, जो भारत के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पॉलीमैटेक कंपनी को सेमीकंडक्टर निवेश के लिए मात्र तीन महीनों में जमीन आवंटित कर एनओसी जारी की गई और अब कंपनी ने 1,143 करोड़ रूप के प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ कर दिया है, जहां प्रतिवर्ष 10 अरब चिप उत्पादन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप

कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में क्रांतिकारी पहल

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि रावघाट से जगदलपुर तक 3,500 करोड़ रूप की रेललाइन की मंजूरी मिल चुकी है। कोठागुड से किरंदुल तक रेललाइन पर सर्वे शुरू हो गया है और खरसिया-परमालकसा रेललाइन औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। जलमार्ग संबलपुर से नवा रायपुर तक आरंभ होगा। एयर कार्गो सेवाएं भी सक्रिय हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एआई डाटा सेंटर पार्क देश का पहला पार्क है। फार्मा सेक्टर में फार्मा हब और मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है। टेक्सटाइल और फार्मा में विशेष अनुदान उपलब्ध है।

ने स्थापित करना है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 विकसित किया गया है। यह प्रणाली ऑनलाइन आवेदन, विभागीय अनुमोदन और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी और तेज है कि क्लिक में प्राप्त हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में चल रहे व्यापक विकास और सुरक्षा अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का संपूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है, ताकि सभी प्रभावित क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास की नई शुरुआत हो सके।

मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। इससे अनुमतियों में लगने वाला समय घटकर रिकॉर्ड समय में आएगा। यह ईज ऑफ इडिंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल

युवाओं को अवसर, निवेशकों को विश्वास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में अगले पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, फार्मा, एआई, डिफेंस, ऊर्जा और मेडिकल टूरिज्म - इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में निवेश करें। यहां हर सुविधा और भरोसे के साथ विकास में सहभागी बनें। हम मिलकर विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उद्योगों के लिए सरल, पारदर्शी और तेज प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से निवेशकों को आवश्यक स्वीकृतियाँ अब न्यूनतम समय में प्राप्त होंगी, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल और मजबूत होगा।

उन्होंने भरोसा जताया कि नई औद्योगिक नीतियों और सहज अनुमतियों की व्यवस्था से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। उद्योग मंत्री देवांगन ने उपस्थित उद्यमियों से अपील की कि वे छत्तीसगढ़ में निवेश कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आर्बटन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 11 प्रमुख कंपनियों से प्राप्त 1 लाख 23 हजार 73 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए उन्हें इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा, जिससे 20 हजार 627 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जिन निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा गया उनमें मेसर्स साराडा हाइड्रोपावर रायपुर, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स

बस्तर और सरगुजा : विकास की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अब 'विकसित बस्तर' के सपने को साकार कर रहा है। 90,000 युवाओं को कौशल विकास और 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। यहां विशेष निवेश प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। बस्तर में अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए बस्तर दशहरा का पंजीकरण कराया जा रहा है। तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज और बस्तर टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। आदिवासी उद्यमियों के लिए रॉयल्टी रिडबर्समैंट और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

इंटेलिजेंस मटेरियल्स लिमिटेड चेंगापट्टू तमिलनाडू, मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता, मेसर्स ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तरप्रदेश, मेसर्स एसजी ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स ज़िंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, मेसर्स ज़िंदल पावर लिमिटेड (थर्मल पावर), मेसर्स ज़िंदल पावर लिमिटेड (सोलर पावर) और मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार, सीजी स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल तथा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया सहित अनेक उद्योग प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

“ मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। ”

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



बेमिसाल खेती की मिसाल बनाओ

फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियाँ

- 23+ करोड़ किसान भाई-बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ
- ₹ 1.75+ लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया
- 78+ करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल द्वारा पारदर्शी एवं त्वरित दावा भुगतान

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025



देशव्यापी हेल्पलाइन 14447



प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना



बीमा भागीदार



अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र

क्रॉप इश्योरेंस ऐप <https://play.google.com>

पोस्ट ऑफिस

बैंक शाखा

@PMFBY

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें